रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924
No. 149] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

सा. का. नि. 239 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 189

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2002

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2002 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि के पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

	राज्य	रु. लाख में
	(1)	(2)
1.	आन्ध्र प्रदेश	19691.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	947.00
3.	असम	7992.00
4.	बिहार	2636.50
5.	छत्तीसगढ़	2163.00
6.	गुजरात	11701.49
7.	हरियाणा	6403.00
8.	हिमाचल प्रदेश	3424.00
9.	झारखंड	4465.00
10.	कर्नाटक	5872.00
11.	केरल	8603.61
12.	मध्य प्रदेश	4932.00
13.	महाराष्ट्र	12380.00
14.	मेघालय	310.00
15.	नागालैंड	247.92
16.	उड़ीसा	6465.75
17.	पंजाब	9664.00
18.	राजस्थान	12225.75
19.	सिक्किम	495.34
20.	तमिलनाडु	8083.00
21.	त्रिपुरा	659.17

(1)		(2)
22.	उत्तर प्रदेश	13521.06
23.	उत्तरांचल	2992.59
24.	पश्चिमी बंगाल	3981.00

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि इस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो, अतिशेष, राज्य की विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 2001 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय राशियों की कोई राशि संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2001 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के. आर. नारायणन,

राष्ट्रपति।"

[फा. सं. 19(3)/2002-विधायी-1]

के. एन. चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2002

G.S.R. 239(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 189

The Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2002

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3, Order, 2002.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3 (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2001, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified below, the sums specified against it, as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood and hailstorm in the States :—

	State	Rupees in lakhs
	(1)	(2)
1.	Andhra Pradesh	19691.00
2.	Arunachal Pradesh	947.00
3	Assam	7992.00
4.	Bihar	2636.50
5.	Chhattisgarh	2163.00
6.	Gujarat	11701.49
7.	Haryana	6403.00
8.	Himachal Pradesh	3424.00
9	Jharkhand	4465.00
10	Karnataka	5872.00
11.	Kerala	8603.61
12.	Madhya Pradesh	4932.00
13.	Maharashtra	12380.00
14.	Meghalaya	310.00
15.	Nagaland	247.92
16.	Orissa	6465.75
17.	Punjab	9664.00
18	Rajasthan	12225.75
19	Sikkim	495.34
20.	Tamil Nadu	8083.00
21.	Tripura	659.17
22.	Uttar Pradesh	13521.06
23.	Uttaranchal	2992.59
24.	West Bengal	3981.00

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2001 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above :

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of this year, is lower than the sums specified above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2001 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2001.

K. R. NARAYANAN,

PRESIDENT."

[F No. 19(3)/2002-L.I.]

K. N. CHATURVEDI, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054